

Tazkira (Quarterly)



तذکرہ
(سه ماہی)



तज़किरा (तिमाही)

दिसंबर 2024-फरवरी 2025

वर्ष -1 अंक -2

मूल्य : ₹ 100

**अंक-1, वर्ष-2**

प्रधान संपादक:	असगर मेहदी
संपादक:	फ़रज़ाना महदी
संपादक (कला एवं शहज़ाद रिज़वी)	
संपादक मण्डल:	नदीम हसनैन, राकेश कुमार मिश्र, कौशल किशोर, डॉ. बिभाष कुमार श्रीवास्तव वीरेंद्र त्रिपाठी, (क्रानूनी सलाहकार) अलीज़ा मेहदी, ज़ाहिद खान
लेज़र टाइप सेटिंग:	डीप इंक, लखनऊ
मूल्य:	एक प्रति ₹ 100.00
संपर्क:	फ़र्स्ट फ़्लोर सी बी चैंबर्स, वी मार्ट के सामने, तहसीन गंज तिराहा, हरदोई रोड, लखनऊ 226003

समस्त क्रानूनी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश होगा।

अनुक्रम

सम्पादकीय	4
इज़हार	8
विमर्श	
मुताज़िला: इस्लाम में तर्क और इस्तदलाल की धाराओं का उरुज और ज़वाल: भाग -2	24
असगर मेहदी	
आर्य प्रश्न	52
राकेश मिश्रा	
साम्प्रदायिकता के सवाल	75
कैवल भारती	
डॉक्टर ज़ाकिर नायक और वैश्विक कॉर्पोरेट	85
अब्बास शाह	
जस्टिस हैदर अब्बास: एक क्राबिल ए तकलीद ज़िंदगी	96
शहज़ाद रिज़वी	
मनमोहन सिंह: एक सौम्य अर्थशास्त्री	102
रफ़त फ़ातिमा	
अदब और साहित्य: कहानी	
इंसानी नस्ल	106
नासिरा शर्मा	
अब शायद ही...!!	118
चित्रा पंवार	
रात भर का ख़्वाब	136
फ़रज़ाना महदी	
कविता/नज़्म	

कैफ़ी आजमी	150
गौहर रज़ा	152
मक़बूल जायसी	154
ओम प्रकाश 'नदीम'	156
सीमा आज़ाद	158
संस्कृति	
इब्राहिम अलक़ाज़ी और आधुनिक रंगमंच का तसव्वुर जाहिद ख़ान	163
फ़िल्मों में मुस्लिम चित्रण: वे तो मुसलमान हैं इक़बाल रिज़वी	176
समीक्षा	
ऑरिजिन ऑफ़ मुस्लिम कॉन्शिएन्सेस इन इंडिया असगर मेहदी	192
'शाहीन बाग़' लोकतंत्र की नई करवट डॉ. उषा राय	234
कर्बला दर कर्बला आशीष सिंह	249
स्टाप प्रेस - ग़ाज़ा में जंग बंदी	

सम्पादकीय

22 सितंबर 2024 को जब तज़क़िरा के पहले अंक का रस्मे इजरा हुआ तो जिस क्रदर गर्मजोशी से स्वागत किया गया, वह हमारी उम्मीदों से 'सिवा' था। इस प्रतिक्रिया से उत्साहित होकर हमने अगला अंक प्रिंट फ़ार्म में लाने का फ़ैसला किया। इस संबंध में हम डीप इंक पब्लिकेशन्स को हार्दिक धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस संबंध में सहायता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है। हमें उम्मीद है कि तज़क़िरा के इस मुद्रित अंक का भी गर्मजोशी से स्वागत किया जाएगा और ज़ी-फ़हम पाठकों द्वारा स्वीकार किया जाएगा। जैसा कि हमने वादा किया था कि तज़क़िरा में प्रकाशित सामग्री ऐसी होगी जो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक टेम्परामेन्ट और इतिहास की समझ वाले मूल्यों के आधार पर एक पुल का निर्माण करेगी, इस अंक में इसी क्रिस्म की सामग्री को जगह दी गई है। हमने पहले अंक में ज़ाहिर किया था कि हमारा मुख्य उद्देश्य विमर्श और सार्थक संवाद का माहौल बनाना है, जहाँ विशेष रूप से मुस्लिम दुनिया से संबंधित 'समझ' पर चर्चा की जाए।

पिछले तीन महीनों में कई बड़ी घटनाएँ हुई हैं। विश्व परिदृश्य पर ट्रम्पवाद के दुबारा उरुज (उदय) और असद के ज़वाल (पतन) प्रमुख हैं। इज़हार कॉलम में असद के ज़वाल के घटनाक्रम का मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। लेकिन यहाँ पर भारत की प्रतिक्रिया को सामने रखना उपयुक्त होगा, जिसने “शांतिपूर्ण और

समावेशी सीरियाई नेतृत्व वाली राजनीतिक प्रक्रिया“ की मांग की है, जो “समाज के सभी वर्गों के हितों और आकांक्षाओं“ का सम्मान करती है। क्या इस तरह का उपदेश घर पर देखा जाता है? जवाब है कदापि नहीं!

यूपी मदरसा कानून, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मैनॉरटी स्टेटस, बुलडोज़र (अ)न्याय और क़दीम मस्जिदों की खुदाई और सर्वे जैसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप सकारात्मक और स्वागत योग्य है। मदरसा जजमेंट के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले में कहा कि राज्य द्वारा धार्मिक सहिष्णुता को सामने रखने कि ज़रूरत है क्योंकि अनुच्छेद 25 से 30 में धर्मनिरपेक्षता का दूसरा यही पहलू शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि 'मदरसा शिक्षा को मान्यता और विनियमित करके, राज्य विधायिका अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की रक्षा के लिए सकारात्मक कार्यवाही करती है। तज़क़िरा संपादकीय दो मामलों की ओर इशारा करता है- बुलडोज़र न्याय और राजनीतिक एजेंडे के साथ किए जा रहे सर्वे जिनमें निचली अदालतों और स्थानीय अधिकारियों के बीच ग़ज़ब का समन्वय देखने को मिलता है।

जी एन साईबाबा, ज़ाकिर हुसैन, श्याम बेनेगल, मनमोहन सिंह और बिप्सा सिधवा के दुखद निधन अहम हैं। बिप्सा सिधवा विभाजन और महिलाओं की स्थिति पर वाक़ई एक कमज़ोर समाज की मुखर आवाज़ थीं।

1947 के विभाजन ने राष्ट्रवाद की अतार्किक और संकीर्ण अवधारणाओं के कारण दो राज्यों (अब बांग्लादेश सहित तीन) का निर्माण किया। ऐसी धाराएँ रही हैं

जो राष्ट्रीयता को धर्म से जोड़ती हैं, इस अवधारणा को धीरे-धीरे भारत में स्वीकृति मिली और पाकिस्तान ने दबाव में आकर इस्लामिक राष्ट्र बनने का विकल्प चुना। वर्तमान परिदृश्य यह है कि उपमहाद्वीप घातक धार्मिक राष्ट्रवाद (फ़ासीवाद) के सामने कमज़ोर हो गया है। भारत के संदर्भ में कहें तो बहुसंख्यकवाद स्थापित हो चुका है और जो राज्य की कार्यप्रणाली से स्पष्ट है। इसके आलोक में इस अंक में कंवल भारती का लेख 'साम्प्रदायिकता के सवाल', निसार अहमद की किताब व गौरी नाथ के उपन्यास की समीक्षाएं अहम हैं। विभाजन सिंड्रोम के संक्रमण का नतीजा है 'सीएए-एनआरसी' जिसके खिलाफ़ समाज ने एकजुट होकर 'शाहीन बाग़' जैसे घटनक्रम के ज़रिए प्रतिक्रिया दी। इस संबंध में भाषा सिंह की किताब की समीक्षा को जगह दी गयी है।

इस अंक के विमर्श कॉलम में 'मुताज़िला तहरीक: उरुज व ज़वाल' के हवाले से विस्तृत लेख के दूसरे और अंतिम भाग को रखा गया है। इसके साथ ही आर्यों के भारत आगमन से संबंधित लेख 'आर्य प्रश्न' को जगह देना का उद्देश्य स्वयं में स्पष्ट है। धर्म और सरमायादारी के गठजोड़ के संदर्भ में एक लेख 'डाक्टर ज़ाकिर नायक और वैश्विक कारपोरेट' शीर्षक से रखा गया है। दिसम्बर माह में जन सरोकारों से जुड़ी शख़िसयत जस्टिस् हैदर अब्बास का निधन अफ़सोसनाक वाक़िया है, जिसके लिये ज़रूरी था कि उन पर एक लेख रखा जाये। पूर्व प्रधान मंत्री पर भी एक लेख है।

साहित्य कॉलम में नासिरा शर्मा, फ़रज़ाना महदी व चित्रा पंवार की कहानियों को जगह दी गयी है। इसके साथ ही कविता/नज़्म में कैफ़ी आजमी, गौहर रज़ा,

मक़बूल जायसी, ओम प्रकाश नदीम, व सीमा आज़ाद रचनाओं को शामिल किया गया है।

संस्कृति कॉलम में इब्राहिम अलक़ाज़ी की शख़्सियत के अनेक पहलुओं से परिचित कराने वाले एक लेख और भारतीय सिनेमा में मुस्लिम समाज को स्टीरियोटाइप से नकारात्मक छवि में गढ़ने की प्रक्रिया पर चर्चा की गयी है।

प्रतिक्रियाओं की उम्मीद के साथ ये अंक पेशे ख़िदमत है....